भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.12.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3797 का उत्तर

पंजाब में चल रही परियोजनाएं

3797. श्री जसबीर सिंह गिलः

डॉ. अमर सिंहः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंजाब में चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक रेल परियोजना की स्थिति क्या है;

(ख) क्या कोई भी परियोजना समय-सीमा से पिछड़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अद्यतन और नवीनीकृत किया जाना है और प्रत्येक पर खर्च की जा रही कुल राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) ब्यास से कादियान और पट्टी से फिरोजपुर के बीच बनने वाली नई रेलवे लाइनों की स्थिति क्या है;

(ङ) क्या अमृतसर स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है और यदि हां, तो कुल कितनी राशि खर्च की जानी है और परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(च) भारत में विशेष रूप से उत्तर भारत में मौजूदा माल वहन गलियारों के भीड़भाड़ की समस्या से निपटने के लिए वर्तमान में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

sk

पंजाब में चालू रेल परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 11.12.2019 को लोक सभा में श्री जसबीर सिंह गिल तथा डॉ. अमर सिंह के अतारांकित प्रश्न सं. 3797 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) एवं (ख): इस समय, पंजाब राज्य में पूर्ण रूप से/ आंशिक रूप से पड़ने वाली 16,100 करोड़ रुपए की लागत की 871 कि.मी. लंबी 14 रेलवे परियोजनाएं (6 नई लाइन और 8 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, इनमें से, 316 कि.मी. लंबी रेल लाइन को यातायात के लिए खोल दिया गया है और मार्च, 2019 तक इस पर 2,184 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इनमें शामिल हैं:

12,414 करोड़ रुपए की लागत वाली 356 कि.मी. लंबी 6 नई लाइन परियोजनाएं, इनमें से 61 कि.मी. लंबी रेल लाइन को यातायात के लिए खोल दिया गया है और जिस पर मार्च, 2019 तक 1,004 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

3686 करोड़ रुपए की लागत वाली 515 कि.मी. लंबी 8 दोहरीकरण परियोजनाएं, जिनमें से 255 कि.मी. लंबी रेल लाइन को यातायात के लिए खोल दिया गया है और जिस पर मार्च, 2019 तक 1,181 करोड़ रूपए का व्यय किया गया है।

बजट सहित परियोजना का विवरण भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात् www.indianrailways.gov.in> Ministry of Railways> Railway Board> About Indian Railways> Railway Board Directorates> Finance (Budget) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं।

2014-19 के दौरान पंजाब राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाएं और संरक्षा संबंधी निर्माण कार्यों हेतु औसत बजट आंबटन को 2009-14 के दौरान 225 करोड़ रु. प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1004 करोड़ रु. प्रतिवर्ष कर दिया गया है, जोकि पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2009-14 (225 करोड़ रु.) के दौरान औसत वार्षिक आबंटन का 446% है।

2019-20 में पंजाब राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाएं और संरक्षा संबंधी निर्माण कार्यों के लिए बजट का कुल आबंटन 1,095 करोड़ रु. है, जोकि 2009-14 के दौरान औसत वार्षिक बजट का 487% है।

किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों) की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की

भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, भूकंप, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, माननीय न्यायालयों के आदेश, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तें आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना-दर-परियोजना तथा साइट-दर-साइट भिन्न-भिन्न होते हैं और परियोजना की समापन अवधि और लागत को प्रभावित करते हैं, जिसे अंतत: समापन स्तर पर निर्धारित किया जाता है।

(ग) एवं (ङ): रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल स्टेशन विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएसडीसी), रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) और अन्य केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों के माध्यम से रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए योजना बनाई है। अमृतसर रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास के लिए आईआरएसडीसी को सौंपा गया है। स्टेशन विकास परियोजना की लागत को स्टेशन के आस-पास की भूमि और खुले क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास से प्राप्त लाभ से पूरा किया जाएगा।

स्टेशन पुनर्विकास परियोजना जटिल प्रकृति की होती है और इसके लिए विस्तृत तकनीकी-वित्तीय व्यवहार्यता अध्ययन और स्थानीय प्राधिकारियों से सांविधिक स्वीकृति अपेक्षित होती है। अत: इस स्तर पर परियोजना की समापन अवधि का संकेत नहीं दिया जा सकता।

(घ): कादियां-ब्यास (39.68 कि.मी.) नई लाइन परियोजना को अपेक्षित अनुमोदनों के अध्यधीन बजट 2011-12 में शामिल किया गया था। इस परियोजना की नवीनतम लागत 890.67 करोड़ रुपए है। कादियां की ओर से परियोजना का अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण (एफएलएस) मई, 2012 में आरंभ किया गया था, परंतु इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों के विरोध और कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं के कारण इसमें विलंब हुआ। अंतत: पुलिस सुरक्षा और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वर्ष 2017 में अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा किया गया। इस परियोजना के लिए 166.68 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण दस्तावेज़ संबंधित विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारियों को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। तीव्र भूमि अधिग्रहण के लिए रेल द्वारा सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारियों को ठेके पर लेने के लिए राज्य राजस्व विभाग को 13 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया है।

फिरोजपुर-पट्टी (मल्लांवाला खास- घरियाला 25.72 कि.मी.) नई लाइन परियोजना को बजट 2013-14 में शामिल किया गया था। इस परियोजना के लिए पंजाब सरकार द्वारा भूमि नि:शुल्क मुहैया कराई जानी है। इस परियोजना की लागत 299.74 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। 70.01 हेक्टेयर भूमि के लिए उप आयुक्त फिरोजपुर को और 95.68 हेक्टेयर भूमि के लिए उप आयुक्त, तरन-तारन को भूमि अधिग्रहण दस्तावेज़ प्रस्तुत कर दिए गए हैं। रेल को पूर्ण बाधा रहित भूमि सौंपे जाने के पश्चात् ही कार्य आरंभ किया जाएगा।

sk

(च) रेल मंत्रालय ने दो समर्पित माल गलियारों (डीएफसी) अर्थात् लुधियाना से सोननगर (1318 कि.मी.) तक पूर्वी समर्पित माल गलियारा (ईडीएफसी), जवाहरलाल नेहरु पोर्ट (जेएनपीटी) से दादरी (1504 कि.मी.) पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (डब्ल्यूडीएफसी) का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है। इन परियोजनाओं पर निर्माण कार्य आरंभ कर दिए गए हैं।

देश में समर्पित माल गलियारे से उच्च परिवहन निर्गत होगा और पारगमन समय में कमी आएगी। समर्पित माल गलियारों को चालू करने के परिणामस्वरूप माल और यात्री सेवाएं बड़े पैमाने पर अलग-अलग होंगी और मौजूदा मार्गों पर भीड़-भाड़ में कमी आएगी, जिससे मौजूदा भारतीय रेल नेटवर्क पर यात्री सेवाओं की कुशलता में सुधार होगा।

******

sk